यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है तो क्या;

(ग) क्या राज्य की प्रचुर खनिज सम्पदा का उपयोग करने का सरकार का कोई निश्चित कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश में अलौह धातुओं के लिए किए गए अन्वेषणों के फलस्वरूप बालाघाट जिले के मालंजखण्ड में 1% ताम्रांश वाली ताम्र अयस्क की 400 लाख टन, बिलासपुर बालाघाट, मण्डला, शाहदोल, दुर्ग, रायगढ़ और सुरगुजा जिलों में 45% ऐलूमिनांश वाली बाक्साइड की 529.8 लाख टन अनुमानित उपलब्ध राशियां निर्धारित की गई हैं।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1969-70 के दौरान मध्य प्रदेश में कोई हवाई सर्वेक्षण नहीं किए। तथापि, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान ने 1968 के दौरान मध्य प्रदेश के पन्ना, चित्तौड़पुर और टीकमगढ़ जिलों में 1600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हवाई चुम्बकीय एकुरणीय सर्वेक्षण किए तथा उनसे सबंधी रिपोर्ट में कुछेक क्षेत्रों में अधिक विस्तृत भूमि अन्वेषणों के लिए सिफारिश की। जनवरी, फरवरी, 1972 में राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश में नर्मदाघाटी के पूरब में 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर उड़ान की गई। इस सर्वेक्षण के चुम्बकीय और स्फुर्णीय आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। हवाई खनिज सर्वेक्षण और समन्वेषण (भारतीय भवैज्ञानिक सर्वेक्षण का स्कंध) ने भी जून, 1972 में मध्य प्रदेश में हवाई सर्वेक्षण किए जिसके परिणाम प्रतीक्षित हैं।

(ग) और (घ). हिन्दुस्तान लिमिटेड मालंजखण्ड ताम्र निक्षेप के विकास के लिए कदम उठा रहा है। भारत एलूमिनियम कम्पनी, कोरबा में, अमरकन्टक और पुटखा पहाड़ बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित एक लाख टन ऐलूमिनियम प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक ऐलूमिनियम प्रायोजना को कार्यान्वित कर रहा है।

मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के निक्षेप

2383. श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में किन-किन क्षेत्रों में लौह अयस्क के निक्षेपों का पता लगाया गया है;

(ख) इन निक्षेपों में लगभग कितना लौह अयस्क मिलने की संभावना हैं; और

(ग) उनके उचित समन्वेषण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के बस्तर, दुर्ग, जबलपुर और ग्वालियर जिलों में लौह अयस्क के बृहद् निक्षेप पाए गए हैं। इन जिलों में लौह अयस्क की निक्षेप-वार उपलब्ध राशियां निम्नलिखित हैं :—

(i)	बैलाडिला (14 निक्षेप)	(बस्तर जिला)	11350 लाख टन (अनुमानित)
(ii)	आरीडुंगरी		170 यथोक्त } (उपर्दर्शित)
(iii)	रौघाट		7500 यथोक्त } (उपर्दर्शित)

(iv) बंजारोंगरी	बस्तर जिला	320 यथोक्त
(v) तेनाथर	,,	120 यथोक्त
(vi) कौण्डपाल	,,	610 यथोक्त
(vii) राजरा	(दुर्ग जिला)	1600 यथोक्त (प्रमाणित)
(viii) दल्ली	,,	
(ix) कोकन	,,	200 यथोक्त
(x) महामाया	,,	500 यथोक्त
(xi) कनहवारा	(जबलपुर जिला)	170 यथोक्त
(xii) अगारिया	,,	140 यथोक्त
(xiii) सरोलीइ	,,	40 यथोक्त
(xiv) घेरा गोसलपुर और बिजोरी	,,	340 यथोक्त
(xv) सान्तऊ हणिहार	(ग्वालियर जिला)	450 यथोक्त (अनुमानित)

इसके अतिरिक्त, खान्दवा, छत्तरपुर और सिंधी जिलों में लघुतर निक्षेप पाए गए हैं।

बैलाडिला निक्षेप सं० 4, 5, 10, 11क, 11ख, 11ग, 13 और 14 में व्यधन द्वारा समन्वेषण सम्पूरित हो चुका है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1971-72 से बस्तर जिले में रौबाट और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण प्रारम्भ किए हैं। कार्य के 1975-76 तक सम्पूरित हो जाने की सम्भावना है।

मध्य प्रदेश में टैक्सटाइल मिलों के उद्योगपतियों द्वारा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजूरी का भुगतान न करना

2384. श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं, कि मध्यप्रदेश टैक्सटाइल मिलों में उद्योगपति मजूरी बोर्ड के निर्णयों के अनुसार मजदूरों को मजूरी नहीं दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति राज्य सरकारों द्वारा करवाई जा रही है। उन से प्राप्त सूचना के अनुसार, 22 कपड़ा मिलों में से, 18 ने सिफारिशों पर क्रियान्विति कर दी है। शेष चार ने या तो सिफारिशों पर आंशिक रूप से क्रियान्विति की है या बिल्कुल भी क्रियान्विति नहीं की है। उनमें से एक रुग्ण इकाई है, एक हाल ही में स्थापित सहकारी इकाई है और सिफारिशों को क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं है तथा दो मिलों के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि वे वित्तीय कठिनाइयों में हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्यप्रदेश के कपड़ा मिलों के कर्मचारियों को समय पर बोनस का भुगतान न किया जाना

2385. श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कपड़ा मिल के